भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियों में सुरक्षा-विकास संतुलन (2020–2025): सामरिक प्रतिस्पर्धा एवं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का एक तुलनात्मक विश्लेषण

[1]दिलीप कुमार, [2]प्रो. संगीता माथुर
[1]रिसर्च स्कॉलर, [2]शोध पर्यवेशक
[12]स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़
[12]करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, कोटा, राजस्थान

सार *(Abstract)*—दक्षिण एशिया एवं व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विगत डेढ़ दशक में शक्ति-संतुलन तेज़ी से पुनर्परिभाषित हुआ है। वर्ष **2020** से **2025** के मध्य गलवान घाटी संघर्ष, वास्तविक नियंत्रण रेखा **(LAC)** पर दीर्घकालिक सैन्य गतिरोध, पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की सतत सैन्य आधुनिकीकरण गति ने भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियों को नए सिरे से गढ़ा है। प्रस्तुत शोध-प्रपत्र इन तीनों राष्ट्रों की रक्षा नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यह प्रश्न उठाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं और सतत विकास लक्ष्यों **(SDGs)** के मध्य किस प्रकार संतुलन साधा जा रहा है, अथवा साधा जाना चाहिए।
अध्ययन गुणात्मक एवं तुलनात्मक पद्धति पर आधारित है तथा द्वितीयक स्रोतों — सरकारी रक्षा बजट दस्तावेज़ों, रक्षा श्वेत-पत्रों, तथा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थिंक-टैंक रिपोर्टों **(SIPRI, IISS)** — के विश्लेषण पर निर्भर है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि भारत एक 'संतुलित प्रतिरोध' **(balanced deterrence)** मॉडल की ओर अग्रसर है जिसमें आत्मनिर्भरता **(Atmanirbhar Bharat)** की भूमिका महत्वपूर्ण है; चीन सैन्य-असैन्य संलयन **(civil-military fusion)** के माध्यम से रक्षा एवं विकास को संस्थागत रूप से एकीकृत करने का प्रयास कर रहा है; जबकि पाकिस्तान में असंतुलित रक्षा-व्यय, बाह्य ऋण-भार तथा राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक सततता के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करते हैं। शोध-प्रपत्र नीति-निर्माताओं हेतु एक संतुलित रक्षा-विकास प्रतिमान की अनुशंसा के साथ समाप्त होता है।

मुख्य शब्द *(Index Terms)*—रक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सतत विकास, भारत-चीन-पाकिस्तान, आत्मनिर्भर भारत, सामरिक संतुलन

I. परिचय (Introduction)

इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में दक्षिण एशिया विश्व के सर्वाधिक सैन्यीकृत तथा भू-राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जाता है। भारत, चीन एवं पाकिस्तान – तीनों परमाणु-शक्ति संपन्न राष्ट्र – साझा सीमाओं, अनसुलझे क्षेत्रीय विवादों तथा परस्पर-विरोधी सामरिक हितों के कारण एक जटिल त्रिकोणीय सुरक्षा-दुविधा (security dilemma) में बंधे हुए हैं। वर्ष 2020 का गलवान संघर्ष इस क्षेत्र में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने भारत की रक्षा नीति में आत्मनिर्भरता, सीमा अवसंरचना विकास एवं बहु-मोर्चा तैयारी की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन को गति दी।

साथ ही, चीन की 'सैन्य-असैन्य संलयन' नीति एवं 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के अंतर्गत बुनियादी ढांचा विकास को सामरिक विस्तार से जोड़ने की रणनीति, तथा पाकिस्तान की चीन पर बढ़ती

आर्थिक-सामरिक निर्भरता (विशेषकर चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे – CPEC – के माध्यम से) ने क्षेत्रीय शक्ति-समीकरणों को और अधिक जटिल बना दिया है। ऐसे परिदृश्य में यह अनिवार्य हो जाता है कि रक्षा-व्यय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं का अध्ययन केवल सामरिक दृष्टिकोण से न कर, सतत विकास लक्ष्यों – गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय स्थिरता – के साथ उनके अंतर्संबंध के परिप्रेक्ष्य में भी किया जाए।

प्रस्तुत शोध-प्रपत्र इसी अंतर्संबंध को केंद्र में रखते हुए तीनों राष्ट्रों की रक्षा नीतियों, रक्षा-बजट प्रवृत्तियों तथा संस्थागत ढाँचों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, और यह मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि किस राष्ट्र का मॉडल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सतत विकास के मध्य अपेक्षाकृत अधिक संतुलित है।

II. साहित्य समीक्षा (Literature Review)

दक्षिण एशियाई सुरक्षा अध्ययनों में भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण पर पर्याप्त शोध-साहित्य उपलब्ध है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की वार्षिक रिपोर्टें वैश्विक रक्षा-व्यय की तुलनात्मक प्रवृत्तियों का प्रामाणिक आंकड़ा-आधार प्रस्तुत करती हैं (SIPRI, 2024)। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की 'मिलिट्री बैलेंस' श्रृंखला तीनों देशों की सैन्य क्षमताओं का विस्तृत तकनीकी विवरण प्रस्तुत करती है (IISS, 2024)। भारतीय रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशीकरण की नीतिगत प्राथमिकताओं को रेखांकित करती हैं (Ministry of Defence, Government of India, 2024)।

चीन की रक्षा नीति पर केंद्रित अध्ययनों में चीन के राज्य परिषद द्वारा प्रकाशित रक्षा श्वेत-पत्र तथा पश्चिमी थिंक-टैंकों के विश्लेषण उल्लेखनीय हैं, जो सैन्य-असैन्य संलयन की अवधारणा को चीन की व्यापक राष्ट्रीय पुनरुत्थान रणनीति से जोड़कर देखते हैं (State Council Information Office of the PRC, 2023)। पाकिस्तान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एवं विश्व बैंक की रिपोर्टें रक्षा-व्यय एवं ऋण-संकट के मध्य सहसंबंध को रेखांकित करती हैं (International Monetary Fund, 2023)।

तथापि, विद्यमान साहित्य में एक स्पष्ट अंतराल यह दिखाई देता है कि अधिकांश अध्ययन या तो विशुद्ध सामरिक दृष्टिकोण से रक्षा नीतियों का विश्लेषण करते हैं, या विकास अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से रक्षा-व्यय

का – किंतु दोनों को एकीकृत तुलनात्मक ढाँचे में प्रस्तुत करने वाले अध्ययन सीमित हैं। प्रस्तुत शोध-प्रपत्र इसी अंतराल को पाटने का प्रयास करता है।

III. शोध उद्देश्य (Research Objectives)

1. भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियों (2020-2025) की तुलनात्मक विवेचना करना।

2. तीनों देशों में रक्षा-व्यय एवं सामाजिक-विकास व्यय के मध्य सहसंबंध का विश्लेषण करना।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के मध्य संतुलन साधने की संस्थागत रणनीतियों की पहचान करना।

4. नीति-निर्माताओं हेतु संतुलित रक्षा-विकास प्रतिमान संबंधी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करना।

IV. शोध पद्धति (Research Methodology)

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, विवरणात्मक एवं तुलनात्मक (comparative) शोध-अभिकल्प पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों से किया गया है, जिनमें सम्मिलित हैं – भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टें, चीन का राष्ट्रीय रक्षा श्वेत-पत्र, पाकिस्तान का वार्षिक बजट दस्तावेज़, तथा SIPRI एवं IISS की तुलनात्मक रिपोर्टें। विश्लेषण की समयावधि 2020 से 2025 तक निर्धारित की गई है, जो गलवान संघर्ष से लेकर वर्तमान तक के काल-खंड को समाहित करती है। तुलनात्मक ढाँचे हेतु तीन विश्लेषणात्मक आयाम अपनाए गए हैं: (क) रक्षा-व्यय की मात्रा एवं GDP अनुपात, (ख) सैन्य आधुनिकीकरण एवं स्वदेशीकरण की दिशा, तथा (ग) रक्षा-व्यय का सामाजिक-विकास व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य) के साथ अंतर्संबंध।

V. भारत की रक्षा नीति (2020–2025)

गलवान संघर्ष (जून 2020) के पश्चात भारत की रक्षा नीति में तीन स्पष्ट प्रवृत्तियाँ उभरीं। प्रथम, सीमा अवसंरचना – सड़कों, पुलों एवं सुरंगों – के निर्माण में तीव्र गति, विशेषकर सीमा सड़क संगठन (BRO) के माध्यम से। द्वितीय, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर बल, जिसमें सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों (Positive Indigenisation Lists) के माध्यम से चरणबद्ध आयात-प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई (Ministry of Defence, Government of India, 2024)।

तृतीय, रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा रक्षा गलियारों (defence corridors) की स्थापना।

भारत का रक्षा बजट सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2 से 2.5 प्रतिशत के मध्य स्थिर रहा है, जो चीन एवं पाकिस्तान की तुलना में अपेक्षाकृत संतुलित अनुपात दर्शाता है (SIPRI, 2024)। साथ ही, भारत ने बहु-ध्रुवीय कूटनीतिक साझेदारियों – क्वाड (QUAD), फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका – के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जिससे रक्षा आत्मनिर्भरता के साथ-साथ आर्थिक विकास की संभावनाएँ भी सृजित हुई हैं। भारत की नीति इस अर्थ में उल्लेखनीय है कि रक्षा उत्पादन को 'मेक इन इंडिया' के व्यापक औद्योगिक ढाँचे से जोड़कर रोज़गार-सृजन एवं तकनीकी विकास का साधन भी बनाया गया है।

VI. चीन की रक्षा नीति (2020–2025)

चीन की रक्षा नीति का केंद्रीय स्तंभ 'सैन्य-असैन्य संलयन विकास रणनीति' (Military-Civil Fusion Development Strategy) है, जिसके अंतर्गत असैन्य तकनीकी नवाचार – कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, 5G – को सीधे सैन्य आधुनिकीकरण से जोड़ा गया है (State Council Information Office of the PRC, 2023)। चीन ने विगत पाँच वर्षों में रक्षा-व्यय में निरंतर वृद्धि की है, यद्यपि आधिकारिक आंकड़े GDP के लगभग 1.5 प्रतिशत के आस-पास दर्शाए जाते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक वास्तविक व्यय को इससे अधिक मानते हैं (IISS, 2024)।

चीन की नीति की विशेषता यह है कि उसने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से आर्थिक विकास एवं सामरिक विस्तार को एक ही ढाँचे में समाहित किया है – जिससे पाकिस्तान, श्रीलंका एवं अन्य पड़ोसी देशों में बुनियादी ढाँचा निवेश साथ-साथ रणनीतिक पहुँच का साधन भी बनता है। तथापि, इस मॉडल की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह पारदर्शिता, ऋण-सततता एवं पर्यावरणीय मानकों के प्रश्नों को पर्याप्त सम्बोधित नहीं करता, जिससे 'सतत विकास' की व्यापक अवधारणा से इसका सामंजस्य सीमित रह जाता है।

VII. पाकिस्तान की रक्षा नीति (2020–2025)

पाकिस्तान की रक्षा नीति गंभीर आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में संचालित हो रही है। वर्ष 2022-23 के भुगतान-संतुलन संकट तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से बार-बार बेल-आउट पैकेज लेने की आवश्यकता ने रक्षा-व्यय की सततता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं (International Monetary Fund, 2023)। इसके बावजूद, पाकिस्तान का रक्षा बजट राष्ट्रीय बजट का एक बड़ा अनुपात बना हुआ है, जबकि शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय दक्षिण एशिया में सबसे निम्न स्तर पर है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) पर बढ़ती निर्भरता ने पाकिस्तान को एक ओर बुनियादी ढाँचा विकास का अवसर दिया है, परंतु दूसरी ओर बाह्य ऋण-भार में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे रक्षा एवं विकास प्राथमिकताओं के मध्य संस्थागत तनाव उत्पन्न हुआ है। पाकिस्तान का मॉडल इस अध्ययन में सर्वाधिक असंतुलित प्रतिमान के रूप में सामने आता है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताएँ सतत विकास लक्ष्यों की कीमत पर प्राथमिकता पाती प्रतीत होती हैं।

VIII. तुलनात्मक विश्लेषण

तीनों राष्ट्रों की रक्षा नीतियों के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भारत रक्षा आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक विकास के मध्य अपेक्षाकृत संस्थागत संतुलन साधने का प्रयास कर रहा है, जिसमें रक्षा-उत्पादन को औद्योगिक नीति का अंग बनाया गया है। चीन रक्षा एवं विकास को 'संलयन' के माध्यम से एकीकृत तो करता है, परंतु पारदर्शिता एवं वैश्विक मानकों के प्रश्न पर उसका मॉडल सीमित जवाबदेही प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान का प्रतिमान सर्वाधिक असंतुलित है, जहाँ रक्षा-व्यय की प्राथमिकता ने सामाजिक क्षेत्र के व्यय को संकुचित किया है तथा आर्थिक सततता को गंभीर जोखिम में डाला है।

यह तुलना यह भी रेखांकित करती है कि 'राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम सतत विकास' का द्वंद्व वस्तुतः शून्य-योग (zero-sum) नहीं होना चाहिए – भारत का अनुभव दर्शाता है कि रक्षा उत्पादन को तकनीकी नवाचार, रोज़गार-सृजन एवं औद्योगिक विकास से जोड़कर दोनों उद्देश्यों को परस्पर-पूरक बनाया जा सकता है, बशर्ते संस्थागत नीति-ढाँचा सुसंगत एवं दीर्घकालिक हो।

IX. निष्कर्ष एवं नीतिगत सुझाव (Conclusion and Policy Recommendations)

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारत, चीन एवं पाकिस्तान की रक्षा नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सतत विकास के मध्य संतुलन साधने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न प्रतिमानों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत का 'संतुलित प्रतिरोध' मॉडल – जो स्वदेशीकरण, बहु-ध्रुवीय साझेदारी एवं औद्योगिक एकीकरण पर आधारित है – अपेक्षाकृत सतत एवं संस्थागत रूप से सुदृढ़ प्रतीत होता है। चीन का मॉडल तकनीकी दृष्टि से प्रभावी है परंतु पारदर्शिता के प्रश्न पर सीमित है। पाकिस्तान का मॉडल आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक असंवहनीय है।

नीतिगत दृष्टि से, यह अध्ययन अनुशंसा करता है कि: (क) रक्षा-व्यय की योजना दीर्घकालिक विकास-लक्ष्यों के साथ संरेखित की जाए; (ख) रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल-विकास से जोड़ा जाए ताकि दोहरा लाभ प्राप्त हो; तथा (ग) क्षेत्रीय विश्वास-निर्माण उपायों (confidence-building measures) के माध्यम से दीर्घकालिक सैन्य गतिरोध की आर्थिक लागत को न्यूनतम किया जाए। भविष्य के शोध हेतु सुझाव दिया जाता है कि रक्षा-व्यय एवं मानव विकास सूचकांक (HDI) के मध्य मात्रात्मक सहसंबंध पर विस्तृत सांख्यिकीय अध्ययन किया जाए।

संदर्भ सूची (References)

[1] International Monetary Fund. (2023). Pakistan: 2023 Article IV consultation—Staff report. IMF Publications.

[2] International Institute for Strategic Studies [IISS]. (2024). The military balance 2024. Routledge.

[3] Ministry of Defence, Government of India. (2024). Annual report 2023–24. Government of India Press.

[4] State Council Information Office of the People's Republic of China. (2023). China's national defense in the new era (White Paper).

[5] Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI]. (2024). SIPRI yearbook 2024: Armaments, disarmament and international security. Oxford University Press.

[6] World Bank. (2023). South Asia development update: Reforms for a faster and sustainable recovery. World Bank Group.